jan Locomotive Works in July, 1962 for fabrication of 1530 tons of steel structure;

(b) whether the contract was assigned to a firm whose quotation was highest of all the seven tenderers who had applied for it;

(c) whether the quantum of work was subsequently revised piecemeal to the benefit of the firm;

(d) if so, the reasons therefor;

(e) whether the entire deal for allotment of the contract to the firm has been investigated and responsibility fixed; and

(f) if not, the reasons therefor?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) Yes, in connection with the Steel Foundry Project.

(b) Initially out of 13 tenderers, three did not quote with "contractor's" steel; of the rest the eighth lowest was accepted for reasons recorded by the Tender Committee.

(c) and (d). A major revision in the quantum of work had to be made in the light of additional requirements worked out subsequently in consultation with technical collaborators for the Steel Foundry. This revision was solely in the interest of the Project.

(e) A high level Committee of Additional Members of the Railway Board was constituted to investigate into the procedural lapses noticed in this case which Committee has since been expanded to include a representative of Audit also as suggested by the Public Accounts Committee in their 72nd Report. This Committee will cover also the points raised in the said Report.

(f) Does not arise.

Export of Lac

515. **Shri K. P. Singh Deo:**
Shri Dhirendranath:
Shri Yogendra Sharma:

Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether it is a fact that export of Lac has declined heavily necessitating the closure of certain factories;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the number of workers affected?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): (a) No, Sir. After a spell of decline during 1964-65 and 1965-66 exports are now showing an upward trend.

(b) and (c). Do not arise.

गजरौला और चंदौसी जंक्शन (उत्तर रेलवे) के बीच रेलवे लाइन

516. श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की उत्तरी सीमा पर चीन के बढ़ते हुए खतरे को ध्यान में रखते हुए गजरौला और चंदौसी जंक्शनों के बीच एक सीधी रेलवे लाइन बिछाने का प्रस्ताव है जिससे कि सभी परिस्थितियों में बिना रोक-टोक के दिल्ली बरेली रेलवे सेक्शन पर रेलगाड़ियां चलती रहें ; और

(ख) क्या रेलवे प्रशासन ने इस रेलवे लाइन को बिछाने की दृष्टि से कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) गजरौला और चन्दौसी के बीच सीधी रेलवे लाइन बिछाने के बारे में रक्षा मंत्रालय से अभी तक इस तरह का कोई सुझाव नहीं मिला है । इसके अलावा, गजरौला से चन्दौसी तक पहले ही रेलवे लाइन मौजूद है और परिचालन की दृष्टि से वहां एक और लाइन बिछाने का औचित्य नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

रेलवे बोर्ड के कार्यालय में संयुक्त निदेशकों के पदों की समाप्ति

517. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के अधीन संयुक्त निदेशकों के 6 पदों को समाप्त कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसी समय 'असिस्टेंट डाइरेक्टर टिकट चैकिंग' का एक नया पद बना दिया गया है : और

(ग) यदि हां, तो ऐसा करने से कितनी बचत हुई है ?

रेलवे मंत्री (श्री वे० गु० पुनाचा) : (क) रेलों में विभिन्न स्तरों पर प्रशासन को गतिशील बनाने और प्रशासन व्यय में किफ़ायत बरतने के उद्देश्य से विभिन्न पदों के कार्य भार और औचित्य की जांच की गयी है । इस सिलसिले में रेलवे बोर्ड के कार्यालय में संयुक्त निदेशकों के 6 पद समाप्त कर दिये गये हैं, लेकिन इन पदों पर काम करने वाले अधिकारियों को उसी ग्रेड में उपयुक्त पदों पर लगा दिया गया है ।

(ख) प्राक्कलन समिति की सिफारिश के अनुसार रेलों के विभिन्न खण्डों पर बिना टिकट यात्रा का अन्दाजा लगाने के लिए अगस्त, 1966 से सहायक निदेशक (टिकट जांच) का एक कनिष्ठ पद बनाया गया है । बिना टिकट यात्रा को कम करने के लिए उपाय निकालने के उद्देश्य से समय-समय पर इस तरह की समीक्षा की जाती है ।

(ग) इसके फलस्वरूप लगभग 1.8 लाख की बचत होने का अनुमान है ।

टेलिविजन सेटों का निर्माण

518. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या औद्योगिक विकास तथा सहकार-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो पार्टियों को, एक कानपुर में, और दूसरी बम्बई में, टेलिविजन सैट बनाने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त दोनों संस्थानों समेत कितने संस्थान इस समय टेलिविजन सैट बना रहे हैं;

(ग) टेलिविजन सैट बनाने का लक्ष्य वार्षिक क्या है; और

(घ) निर्मित टेलिविजन की लागत कितनी है ?

औद्योगिक विकास तथा सहकार कार्य-मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). मैसर्स जे० के० रेयन कानपुर तथा टेलिराड बम्बई द्वारा प्रस्तुत टेलिविजन सेटों के निर्माण की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और प्रत्येक को 10,000 प्रतिवर्ष की क्षमता के आशय-पत्र जारी कर दिये गये है । अन्य 10,000 सेटों की वार्षिक क्षमता लघु उद्योग क्षेत्र के लिये सुरक्षित रखी गई है ।

इन दोनों में से किसी भी एकक ने अभी उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया है किन्तु सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स इन्स्टीट्यूट, पिलानी जो उपर्युक्त फर्मों को तकनीकी जानकारी प्रदान कर रहा है, ने 1000 सेटों का उत्पादन परीक्षण के आधार पर प्रारम्भ कर दिया है । पिलानी इन्स्टीटयूट द्वारा निर्मित इन सेटों का मूल्य 1,350 रु० से लेकर 1,500 रुपये के बीच होगा जो पर्दे के आकार पर निर्भर करेगा ।